

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994

प्रलिस के लिये: गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994, प्रसव पूर्व नदिन तकनीक

मेन्स के लिये: प्रसवपूर्व नदिन और लगे-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित नैतिक एवं कानूनी मुद्दे, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994 के प्रावधान, उद्देश्य, भारत में लगे-चयन गर्भपात के अभ्यास को रोकने में इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दल्लि उच्च न्यायालय ने टपिणी की है कि PCPNDT के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये **गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक** (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques- PCPNDT) अधिनियम के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

- दल्लि उच्च न्यायालय ने यह नरिदेश PCPNDT अधिनियम की वभिन्नि धाराओं के तहत दर्ज एक **प्राथमिकी** को रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

PCPNDT अधिनियम:

- परचय:**
 - गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994 भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिससे **कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गरिते लगानुपात** को रोकने, प्रसवपूर्व लगे चयन को प्रतबिंधित करने लिये अधिनियमित किया गया था।
- उद्देश्य:**
 - इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लगे चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतबिंध लगाना और लगे-चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है।
- प्रावधान:**
 - यह **अल्ट्रासाउंड** मशीन जैसे- प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों के उपयोग को वनियमित करता है और इस प्रकार की मशीनों को केवल आनुवंशिक असामान्यताओं, चयापचय संबंधी विकार, क्रोमोसोमल असामान्यताओं, कुछ जन्मजात विकृतियों, हीमोग्लोबिनोपैथी तथा लगे संबंधी विकार का पता लगाने के लिये उपयोग में लाने की अनुमति देता है।
 - भ्रूण के लगे का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला या केंद्र अथवा क्लिनिक अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण किया जाना नषिद्ध है।**
 - अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के प्रयोग से व्यक्ति द्वारा गर्भवती महिला अथवा उसके रशितेदारों को शब्दों, संकेतों अथवा किसी अन्य तरीके से **भ्रूण के लगे की जानकारी देना नषिद्ध है।**
 - कोई भी व्यक्ति जो नोटिस, सर्कुलर, लेबल अथवा किसी दस्तावेज के रूप में प्रसवपूर्व और गर्भधारण पूर्व लगे चयन संबंधी सुविधाओं का वजिज्ञापन देता है या फरि इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रटि रूप में अन्य मीडिया के माध्यम से वजिज्ञापित करता है, ऐसे व्यक्ति, संस्थान या केंद्र के संचालक को तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध:**
 - इस अधिनियम के तहत अपंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों का उपयोग करना एक अपराध है।
 - इस अधिनियम के तहत लगे चयन नषिद्ध है।
 - इस अधिनियम में नरिदषिट उद्देश्य के अतरिकित किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रसवपूर्व नदिन तकनीक का इस्तेमाल करना अपराध है।
 - इस अधिनियम के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन अथवा भ्रूण लगे का पता लगाने में सक्षम किसी भी अन्य उपकरण की बकिरी, वतिरण, आपूर्ति, करिए पर लेना आदि नषिद्ध है।

लगे-चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ पहल:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:**

- यह अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य **लगि आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना** तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है।

■ बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016:

- यह बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिये प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में लगि-पक्षपाती **लगि चयन के उन्मूलन की दशा में कार्य करता है।**

दिल्ली उच्च न्यायालय की चर्चा का विषय:

■ छापे और बरामदगी में पुलिस की भागीदारी की व्यावहारिकता:

- न्यायालय ने कहा कि हालाँकि PCPNDT नियमों में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि **“जहाँ तक संभव हो”** पुलिस छापेमारी, जब्ती आदि में शामिल न हो, लेकिन इस पहलू की व्यावहारिकता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी कार्रवाई सुविधा केंद्रों/क्लीनिकों पर छापे मारने के लिये **CrPC** के अनुसार होनी चाहिये”।

■ जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियाँ:

- न्यायालय ने पाया कि उपर्युक्त प्राधिकारी को **PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा केंद्रों और सुविधाओं के पंजीकरण की जाँच करने** तथा छापेमारी, रद्द या निलंबित करने की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उसके पास इस अधिनियम के तहत किसी को भी गरिफ्तार करने की शक्ति नहीं है।

- इस अधिनियम के तहत अपराधों को **‘संज्ञेय’** बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस गरिफ्तारी कर सकती है।
- हालाँकि न्यायालय ने अधिनियम को लागू करने में उपर्युक्त प्राधिकरण की भूमिका की प्रभावशीलता के बारे में चर्चा जताई क्योंकि उसके पास गरिफ्तारी की शक्ति नहीं है।

■ सज़ा की कम दर:

- कम दोष सिद्धि दर उन मामलों के प्रतिफलित करती है जिनमें अभियुक्त दोषी पाए जाते हैं और उस अपराध हेतु दोषी पाए जाते हैं जिसके लिये उन्हें आरोपित किया गया था।
- PCPNDT अधिनियम के संदर्भ में इसका मतलब है कि वास्तव में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है।
- यह अपराधियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने और **लगि-चयन गर्भपात के अवैध अभ्यास को रोकने के लिये न्याय प्रणाली की वफादारी को इंगित करता है।**

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के नहितार्थ:

■ पुलिस की जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियों पर स्पष्टता:

- न्यायालय द्वारा उठाई गई चर्चाओं ने अधिनियम को लागू करने में पुलिस की भूमिका के साथ-साथ उपर्युक्त प्राधिकारियों में नहित जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

■ दोषसिद्धि दर में वृद्धि:

- PCPNDT अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की कम दर एक सतत चुनौती रही है और अदालत की टिप्पणी लगि-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद कर सकती है।

प्रसवपूर्व नदिन और लगि-चयनात्मक गर्भपात से जुड़े नैतिक मुद्दे :

■ अधिकारों और मानवीय गरमा का उल्लंघन: लगि-चयनात्मक गर्भपात लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप है जो उनके जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

- यह मानव जीवन के मूल्य और गरमा तथा मानव समाज की विविधता को भी कमजोर करता है।

■ सामाजिक समस्याओं में वृद्धि: समाज पर इसके प्रतिकूल परिणाम देखे जाते हैं जैसे- विषम लगानुपात, बढ़ती तस्करी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुरुषों के लिये विवाह की संभावनाएँ कम होना आदि।

- यह गैर-चिकित्सा उद्देश्यों के लिये प्रसवपूर्व नदिन के उपयोग और अजनमे बच्चे के प्रतिभाता-पति और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की ज़िम्मेदारी को लेकर नैतिक प्रश्न भी उठाता है।

■ हेल्थकेयर तक पहुँच: प्रसवपूर्व नदिन और लगि-चयनात्मक गर्भपात मौजूदा स्वास्थ्य असमानता और अन्य असमानताओं को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले उन समुदायों के लिये जिनकी स्वास्थ्य सेवा और जानकारी तक सीमा है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

222222:

प्रश्न. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करेंगे जो दिखाते हैं कि अनुसूचित जातियों के बीच लगानुपात की तुलना में भारत में जनजातियों में लगानुपात महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल है? (2015)

[स्रोत: द हिंदू](#)

हू इज़ टपिगि द स्केल रपिर्ट: IPES

प्रलिमिन्स के लिये:

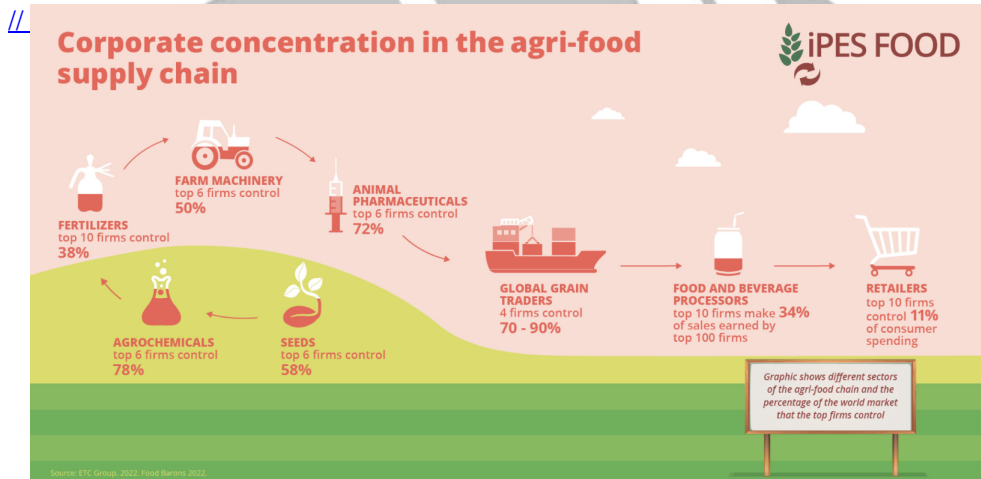
[फूड गवरनेंस](#), [ब्लूवांशिग](#), [CGIAR](#), [खाद्य एवं कृषि संगठन](#), बलि एंड मेलडि गेट्स फाउंडेशन, [संयुक्त राष्ट्र](#)

मेन्स के लिये:

हू इज़ टपिगि द स्केल रपिर्ट: IPES

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (IPES) द्वारा "हू इज़ टपिगि द स्केल" शीर्षक से एक रपिर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे वैश्विक [खाद्य प्रशासन](#) पर कॉर्पोरेट वर्चस्व बढ़ता जा रहा है एवं यह ब्लूवांशिग के बारे में चर्चा बढ़ा रहा है।



ब्लूवांशिग:

- ब्लूवांशिग उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिये गलत सूचना का उपयोग कर रहा है कि एक कंपनी वास्तव में डिजिटल रूप से अधिक नैतिक एवं सुरक्षित है।
 - यह बिल्कुल ग्रीनवाशिग की तरह है लेकिन यह पर्यावरण के बजाय सामाजिक और आर्थिक ज़िम्मेदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
 - ग्रीनवाशिग भ्रामक वणिगण का एक रूप है जिसमें एक कंपनी झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद, नीतियाँ या कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल या लाभकारी हैं, जबकि ये व्यवहार में पर्यावरण की सहायता हेतु बहुत कम या कुछ भी नहीं करते हैं।
- 'ब्लूवांशिग' शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन कंपनियों हेतु किया गया था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एवं इसके सिद्धांतों पर

हस्ताक्षर किये थे लेकिन कोई वास्तविक नीतिगत सुधार नहीं किया था।

- यह कार्य प्रायः कंपनियों द्वारा अपने डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट या नरिधार दावा या [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) की रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में दावा कर किया जाता है।

प्रमुख बंदि

■ खाद्य प्रशासन पर नगिम का प्रभाव:

- प्रशासन के क्षेत्र में वैध अभिनता होने का दावा करने वाली फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- हाल के दशकों में नगिम सरकारों को यह विश्वास दलाने में सफल रहे हैं कि खाद्य प्रणालियों के भवषिय पर होने वाली किसी भी चर्चा में उनकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिये।
- नगिम भागीदारी ने नरिणय लेने पर अधिक प्रभाव वाले वैश्विक खाद्य प्रशासन संस्थानों और नगिमों हेतु धन का एक प्रमुख स्रोत प्रदान किया है।

■ खाद्य प्रशासन में कॉर्पोरेट भूमिका का सामान्यीकरण:

- सार्वजनिक-नजी भागीदारी और बहु-हतिधारक गोलमेज़ (राउंडटेबल्स) द्वारा खाद्य प्रशासन एवं नरिणय लेने में नजी नगिमों की भूमिका को सामान्य कर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक प्रशासन की पहल नजी वतितपोषण पर बहुत अधिक नरिभर हो गई है।

- [संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, 2021](#) को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में कॉर्पोरेट प्रभाव के महत्त्व पर प्रकाश डालने हेतु एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में वर्णित किया गया था।

■ कॉर्पोरेट प्रभाव पर चर्चा:

- नागरिक सामाजिक संगठनों, खाद्य वैज्ञानिकों ने यह चर्चा व्यक्त की है कि खाद्य प्रशासन में नगिमों की बढ़ती भागीदारी से जनता की भलाई और लोगों तथा समुदायों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है।

■ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कॉर्पोरेट प्रभाव:

- नगिमों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक खाद्य प्रशासन को प्रभावित किया है।
- बेहतर पोषण हेतु वैश्विक गठबंधन, खाद्य एवं भूमि उपयोग गठबंधन और पोषण गतिविधियों में वृद्धि करने से वैश्विक खाद्य प्रणालियों के प्लेटफॉर्म में कॉर्पोरेट प्रभाव देखा जा सकता है।
- नजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राजनैतिक और संस्थागत अनुदान, व्यापार और नविश नयिमों एवं अनुसंधान रणनीतियों का नयिमन और वैश्विक खाद्य प्रणालियों के वविधि संरचनात्मक पहलू अन्य न्यून प्रभावी तरीके थे जिनमें खाद्य प्रणाली शासन में कॉर्पोरेट प्रभाव देखा गया था।

■ कॉर्पोरेट भागीदारी बढ़ने का कारण:

- कोवडि-19 महामारी, [यूक्रेन पर रूस के आक्रमण](#) और [खाद्य मुद्रासफ़ीति](#) ने मलिकर कॉर्पोरेट भागीदारी के मुद्दे को बढ़ावा दिया।
- इन संकटों के बाद सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों को नविश की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

■ कॉर्पोरेट भागीदारी की घटनाएँ:

- [अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह \(CGIAR\)](#) खाद्य उद्योग से जुड़े नजी फर्मों और नजी परोपकारी संस्थानों के वतितपोषण पर नरिभर था।
- बलि एंड मेलडि गेट्स फाउंडेशन, जो वर्ष 2020 में CGIAR का दूसरा सबसे बड़ा दानकर्त्ता था, ने लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सरकारों द्वारा व्यक्तितगत रूप से दिये गए योगदान से कहीं अधिक था।
- FAO को अपने पूरे इतिहास में उद्योग साझेदारी के माध्यम से नगिमों के साथ घनषिट सहयोग करने के लिये भी जाना जाता है। हालाँकि इन योगदानों के बारे में वविरण आसानी से उपलब्ध नहीं थे।

वैश्विक खाद्य प्रशासन में अत्यधिक कॉर्पोरेट भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ?

■ सीमति जवाबदेही:

- खाद्य प्रणाली में नजी अभकिर्त्ता जनता या नयिमक नकियाँ के प्रतजिवाबदेह नहीं हो सकते हैं, जसिसे खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थरिता को लेकर अपर्याप्त नगिरानी की आशंका उत्पन्न हो सकती है।
- नजी अभकिर्त्ता भी सार्वजनिक भलाई पर अपने मुनाफे को प्राथमिकता दे सकते हैं, जसिसे हतियों का टकराव हो सकता है जो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थरिता से समझौता कर सकता है।

■ हाइपर नजगि:

- अत्यधिक कॉर्पोरेट भागीदारी से दैनिक लेन-देन डेटा (स्वचालित खाद्य सेवाओं के लिये डिजिटल वॉलेट) को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जसि वे लोगों की खाने की आदतों में हेर-फेर करने हेतु इसे ऑनलाइन प्राप्त जानकारी के साथ जोड़ सकते हैं।

■ लाभों का असमान वतारण:

- नज़ी अभिकर्त्ता लघु किसानों और उपभोक्ताओं की बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादनकर्त्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं जिससे खाद्य प्रणाली से होने वाले लाभ का वितरण असमान हो सकता है।

■ सीमिति पारदर्शिता:

- नज़ी अभिकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले तरीकों, उत्पादों और नीतियों को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किये जाने से हतिधारकों को उनके द्वारा उठाए गए कदमों का खाद्य प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना कठिन हो सकता है।

■ खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति:

- खाद्य प्रणाली का नियंत्रण बगि डेटा टेक्नोलॉजीज़ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हाथों में चले जाने से इससे खाद्य असुरक्षा की स्थिति और गंभीर हो सकती है, साथ ही पर्यावरणीय क्षरण में भी वृद्धि हो सकती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता खाद्य पारस्थितिकी तंत्र की पुनर्संरचना करने की दृष्टि में अग्रसर है, डिजिटल अवसंरचना के रूप में रोबोटिक ट्रैक्टर और ड्रोन के आगमन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जाने हेतु बाध्य हो जाएंगे।

सुझाव:

- मानवाधिकारों पर आधारित एक ठोस शिकायत नीति और नए कार्यतंत्र की स्थापना की जानी चाहिये जो जन संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और अन्य नागरिक समाज अभिकर्त्ताओं को अपनी शर्तों पर खाद्य प्रशासन में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता हो।
- जन संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के दावों एवं प्रस्तावों के लिये स्वायत्त प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाना चाहिये, विशेष रूप से उनके लिये जो हाथियों के समुदायों के लिये एजेंसी का निर्माण करते हैं।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

आदर्श आचार संहिता

प्रलम्ब के लिये:

[आदर्श आचार संहिता](#) (MCC), [भारत निर्वाचन आयोग](#) (ECI)

मेन्स के लिये:

MCC के विकास में ECI की भूमिका, आदर्श आचार संहिता - चुनावों में महत्त्व और इसकी आलोचना

चर्चा में क्यों?

जैसे-जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दल एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगा रहे हैं।

- [आदर्श आचार संहिता \(MCC\)](#) के उल्लंघन को लेकर पार्टियों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से शिकायत की है।

आदर्श आचार संहिता (MCC):

■ परिचय:

- यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के नियमन तथा स्वतंत्र और नृषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं नृषिपक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।
- आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।

■ विकास:

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी।

- इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में नरिवाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।
- वर्ष 1991 में चुनाव के नियमों के बार-बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने MCC को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया।

■ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों हेतु MCC:

◦ प्रतर्बिधति:

- राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पछिले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमति होनी चाहिये।
- जातगित और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रशिवत देने या डराने और किसी के वचिरों का वरिध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतविधियाँ पूरणतः नषिदिह हैं।

◦ बैठकें:

- पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना चाहिये ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।

◦ जुलूस:

- यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतर्निधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमत नहीं है।

◦ चुनाव के दिन:

- केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमत होती है।
- मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिये।
- उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज़ पर होगी और उसमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा।

◦ प्रेक्षक:

- कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को कर सकता है।

◦ सत्ताधारी पार्टी:

- MCC ने सत्ताधारी पार्टी के आचरण को वनियमति करते हुए वर्ष 1979 में कुछ प्रतर्बिधों को शामिल किया। मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएँ और चुनाव कार्य पृथक होने चाहिये अथवा चुनाव कार्य के लिये आधिकारिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- पार्टी को सरकारी संसाधनों की कीमत पर वजिज़ापन देने अथवा चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये उपलब्धियों के प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिये।
- आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिये, सड़कों के निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदिका वादा नहीं करना चाहिये। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों तथा वशिरामगृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिये।

◦ चुनावी घोषणापत्र:

- भारतीय नरिवाचन आयोग का नरिदेश है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव (संसद/राज्य वधिनमंडल) के लिये चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय नमिनलखिति दशिन-नरिदेशों का पालन करना आवश्यक है:
- इस चुनाव घोषणापत्र में संवधिन में नहिती आदर्शों और सदधिधंतों के खलिफ कुछ भी नहीं होगा।
- राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिये जनिसे चुनाव प्रकरिया की शुद्धता धूमलि होने या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो।
- घोषणापत्र में वादों के औचित्य को प्रतर्बिधिति करना चाहिये और इसके लिये वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों एवं साधनों को व्यापक रूप से इंगति करना चाहिये।
- जनप्रतर्निधित्व अधनियम, 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहु-चरणीय चुनावों के लिये नरिधारित प्रतर्बिधात्मक अवधि के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

MCC में कुछ हालिया परिवर्द्धन:

- ECI द्वारा अधसूचित अवधि के दौरान ओपनिथिन पोल और एग्जटि पोल का वनियमन।
- मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रटि मीडिया में वजिज़ापनों पर प्रतर्बिध जब तक कि वषिय-वस्तु स्क्रीनगि समतियाँ द्वारा पूरव-प्रमाणित न हो।

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022)

जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेरिस समझौते की वफािलता

परिचय के लिये:

[पेरिस समझौता](#), भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य, [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय](#), [स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट](#)

मेन्स के लिये:

हू इज़ टपिंग द स्केल रिपोर्ट: IPES

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO)** ने **स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट** जारी की जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर **पेरिस समझौता** अपने **एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी** रहा है।

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर चल रही वैश्विक वार्ता का केंद्रीय बटु है, इस पर वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किये गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते का प्रदर्शन:

- जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता:**

- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरांत **पछिले आठ वर्ष (2015-2022)** **वर्ल्ड स्तर पर लगातार सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।**
 - यदि पिछले तीन वर्षों में **ला नीना** की घटना नहीं हुई होती, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी।
 - अद्यतन **2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य (जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है)** के संदर्भ में **वर्ल्ड स्तर पर अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं है।
 - जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट के लिये मुख्य रूप से ज़िम्मेदार कारक है**, यह पेरिस समझौते के तहत इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतिबद्धता में सफल नहीं रहा है।
 - जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिये न तो NDC और न ही आपदा जोखिम में कमी और जलवायु जोखिम प्रबंधन योजनाएँ कारगर रही हैं।**

- सुझाव:**

- पेरिस समझौते** के पूरक हेतु **जीवाश्म ईंधन संधि के रूप में एक नया वैश्विक ढाँचा पेश किया जाना चाहिये।**
- अधिकांश औद्योगिक और उत्सर्जन उत्पादक देशों को पेरिस समझौते की शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य किया जाना चाहिये।
- तीव्र और तेज़ कार्बन कटौती के साथ त्वरित जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि साधन, सूचना और समाधान मौजूद हैं।
- अनुकूलन और लचीलापन में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर देशों और समुदायों के लिये जिन्होंने संकट पैदा करने में कम-से-कम योगदान दिया है।**

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता:

- यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)** के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से नीचे तक सीमित करना है, साथ ही वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने का लक्ष्य है।
- इसने **क्योटो प्रोटोकॉल** के रूप में प्रसिद्ध पूर्व जलवायु परिवर्तन समझौते का स्थान लिया है।
- पेरिस समझौता **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने और जलवायु परिवर्तन को उजागर**

करने के अपने प्रयासों में विकासी देशों को सहायता प्रदान करने हेतु एक साथ काम करने के लिये देशों के संदर्भ में रूपरेखा तैयार करता है।

- पेरिस समझौते के तहत **प्रत्येक देश** को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिये अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए उसे **प्रत्येक 5 वर्ष में NDC को प्रस्तुत और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है।**

- NDC, देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने हेतु लिया गया एक वचनपत्र है।

- **भारत के अद्यतन NDC:**



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????:

प्रश्न. "अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions)" पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- A. युद्ध-प्रभावित मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिया गया वचन
- B. जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना
- C. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान
- D. धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना

उत्तर : (B)

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

- 1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे और यह 2017 में प्रभावी होगा।
- 2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिकी स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
- 3. विकासित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष \$1000 बिलियन दान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1 और 3
- b. केवल 2
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान

प्रलिमिंस के लिये:

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, [WHO](#), [सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज](#)

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिये **7वाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts- NHA) अनुमान (2019-20)** जारी किया है, जसि **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र** द्वारा तैयार किया गया है।
 - NHA अनुमान **वर्शिव स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO)** द्वारा प्रदान किये गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के आधार पर लेखांकन ढाँचे का उपयोग कर तैयार किये जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र:

- इसकी स्थापना वर्ष 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission- NRHM) के तहत तकनीकी सहायता हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका जनादेश नीति एवं रणनीति तैयार करने, राज्यों हेतु तकनीकी सहायता जुटाने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) हेतु क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान का समर्थन करना है।

प्रमुख बिंदु

स्वास्थ्य संकेतक	परिभाषा	वर्कसिती रुझानों के आँकड़े
पॉकेट व्यय (OOPE) से बाहर	OOPE, स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त करने के बिंदुओं पर परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाने वाला धन है। यह तब होता है जब न तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं, न ही व्यक्ति को किसी सार्वजनिक या निजी बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है।	कुल स्वास्थ्य व्यय में OOPE की भागीदारी वर्ष 2014-15 के 62.6% से घटकर 2019-20 में 47.1% हो गई है।
सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)	जब धन को सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार की निम्नतम स्वास्थ्य प्रणाली के लिये दिया जाता है तब GHE केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित एवं प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत खर्च करता है, जिसमें अर्द्ध-सरकारी संगठन और दानकरता शामिल हैं।	देश की कुल GDP में GHE की भागीदारी 1.13% (2014-15) से बढ़कर 1.35% (2019-20) हो गई ।
सामान्य सरकारी व्यय (GGE)	यह सरकारी हिससे का अनुपात है। यह सामान्य सरकारी व्यय में स्वास्थ्य देखभाल के लिये व्यय और स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सरकार की प्राथमिकता को इंगित करता है।	IGGE में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय का भाग लगातार 3.94% से बढ़कर 5.02% हो गया है ।
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)	वर्तमान पूंजी का गठन करता है बाहरी नधियों सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किये गए व्यय।	वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में GHE की हिससेदारी 29% से बढ़कर 41.4% हो गई है।
सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)	स्वास्थ्य पर एसएसई की हिससेदारी, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा, सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतर्पित और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शामिल हैं।	स्वास्थ्य पर एसएसई की हिससेदारी वर्ष 2014-15 के 5.7% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 9.3% हो गई है ।
निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय (PHIE)	PHIE स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से खर्च करता है, जहाँ परिवार या व्यक्ति एक विशिष्ट स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किये जाने के लिये प्रीमियम का भुगतान करते हैं।	कुल स्वास्थ्य व्यय में से निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय वर्ष 2013-14 के 3.4% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 7% हो गया है।
स्वास्थ्य के लिये बाहरी/दाता अनुदान	यह दाताओं की सहायता से देश के लिये उपलब्ध सभी नधियों को संघटित करता है।	यह वर्ष 2013-14 के 0.3% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 0.5% हो गया है।

आगे की राह

- राज्य सरकारों को **स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को बढ़ाकर अपने कुल बजट का लगभग 8% प्रतिशत तक** करना चाहिये, वर्तमान में कई राज्यों के लिये यह आँकड़ा 4-5% है और "यह खर्च नागरिकों की सहायता के समग्र लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिये"।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के पैटर्न को बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्राथमिक एवं पूर्ण स्वास्थ्य के लिये निवारक और प्रचारात्मक उपायों पर ध्यान दिया जा सके।
- पंद्रहवें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च को वर्ष **2025 तक जीडीपी के प्रतिशत से 2.5**

प्रतश्चित करने की नीतगित सफिरशि की गई है ।

- वर्तमान में 20% आबादी के पास सामाजिक और नजि स्वास्थय बीमा है, जबकशेष 30%, जनिहें "मसिगि मडिलि" के रूप में जाना जाता है, के पास कोई स्वास्थय बीमा नहीं है ।

हेल्थकेयर से संबंधति पहल:

- [राष्ट्रीय स्वास्थय मशिन ।](#)
- [आयुषमान भारत ।](#)
- [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(AB-PMJAY\) ।](#)
- [राष्ट्रीय चकितिसा आयोग ।](#)
- [प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलसिस कार्यक्रम ।](#)
- [जननी शशि सुरकषा कार्यक्रम \(JSSK\) ।](#)
- [राष्ट्रीय बाल स्वास्थय कार्यक्रम \(RBSK\) ।](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

धार्मकि स्वतंत्रता

प्रलिमिस के लयि:

[धार्मकि स्वतंत्रता](#), अनुच्छेद 25-28, [मौलिक अधिकार](#), [NIA](#), [CBI](#), [जबरन धर्मांतरण](#)

मैस के लयि:

धार्मकि स्वतंत्रता और संबंधति संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमलिनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचकिा के प्रत्युत्तर में कहा है कभारतीय संवधान का [अनुच्छेद 25 \(धार्मकि स्वतंत्रता\)](#) प्रत्येक नागरकि को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है ।

- याचकिाकर्त्ता ने याचकिा में [मौलिक अधिकारों](#) का उल्लंघन कर तमलिनाडु में जबरन धर्मांतरण करने की घटनाओं के बारे में शकिायत की थी ।

मामला:

- याचकिाकर्त्ता ने [NIA \(राष्ट्रीय जाँच एजेंसी\)/CBI \(केंद्रीय जाँच ब्यूरो\)](#) द्वारा तमलिनाडु में एक 17 वर्षीय लड़की की मृत्यु के "मूल कारण" की जाँच करने की मांग की, याचकिाकर्त्ता का आरोप है कलिड़की को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लयि मजबूर कयिा गया था । याचकिा में तर्क दयिा गया था कजबरन या धोखे से धर्मांतरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ।
- तमलिनाडु सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कमिशनरयिों (प्रचारकों) द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार करने को अवैध रूप से नहीं देखा जा सकता है क्योंकिसंवधान प्रत्येक नागरकि को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है ।
 - यदउनका अपने धर्म के प्रसार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थय के वपिरीत है और [संवधान के भाग III](#) के अन्य प्रावधानों के खलिाफ है तो इसे गंभीरता से लयिा जाना चाहयि ।

धर्म की स्वतंत्रता:

परचिय:

- प्रत्येक नागरकि को अधिकार है कविह अपनी पसंद के धर्म का प्रचार-प्रसार, अभ्यास करने के लयि स्वतंत्र है ।
 - यह सरकार के हस्तकषेप के भय के बनिा सभी को अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का अवसर प्रदान करता है ।

- लेकिन साथ ही राज्य द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करे।

■ आवश्यकता:

- भारत विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। यू.एस.सी. के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, **4,641,403 लोग ऐसे हैं जो छह प्रमुख धर्मों- हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्मों के अलावा अन्य धर्मों का पालन करते हैं।**
- इसलिये इतनी विविधतापूर्ण आबादी के साथ विभिन्न धर्मों और विश्वासों का पालन करते हुए प्रत्येक धर्म की आस्था के संबंध में अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित करना आवश्यक हो जाता है।

■ धर्मनिरपेक्षता:

- 1976 में **42वें संविधान संशोधन** द्वारा **संविधान की प्रस्तावना** में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है।
- अहमदाबाद **सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1975)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ न तो ईश्वर वरिधी है और न ही ईश्वर समर्थक। यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के मामलों में ईश्वर की अवधारणा को समाप्त करते हुए धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाए।

■ धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान:

- **अनुच्छेद 25:** यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 26:** यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
- **अनुच्छेद 27:** यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिये करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है।
- **अनुच्छेद 28:** यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है।

धर्मनिरपेक्षता, भारत बनाम संयुक्त राष्ट्र:

- भारत धर्म के प्रति 'तटस्थता' और 'सकारात्मक भूमिका' की अवधारणा का अनुसरण करता है। राज्य धार्मिक सुधार लागू कर सकता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है तथा धार्मिक मामलों पर नीतियों का निर्माण कर सकता है।
- अमेरिका धर्म के मामलों में 'अहस्तक्षेप' के सिद्धांत का पालन करता है। राज्य धार्मिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायिक घटनाएँ:

■ बज्रिय इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):

- इस मामले में यहोवा के साक्षी संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया कि यह उनके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने नरिणय दिया कि यह नषिकासन मौलिक अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

■ आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1983):

- न्यायालय के नरिणय के अनुसार, आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है और **सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास नहीं है।**

■ एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मस्जिद इस्लाम की एक आवश्यक प्रथा नहीं है, अतः एक मुसलमान खुले स्थान पर कहीं भी नमाज (प्रार्थना) कर सकता है।

■ राजा बरिकाशोर बनाम उड़ीसा राज्य (1964):

- इसमें जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसने पुरी मंदिर के मामलों के प्रबंधन के प्रावधानों को इस आधार पर अधिनियमित किया था कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम केवल सेवा पूजा के धर्मनिरपेक्ष पहलू को विनियमित करता है, अतः **यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है।**

नोट:

- कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे

राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किये हैं।

- मार्च 2022 में हरियाणा राज्य विधानसभा ने प्रलोभन, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ [हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022](#) पारित किया।
- अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने [हिमाचल प्रदेश धर्म सवतंत्रता \(संशोधन\) अधिनियम, 2022](#) भी पारित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अपराध बनाने की मांग की गई थी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/02-05-2023/print>

